भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2850

उत्तर देने की तारीख 17 दिसंबर, 2025 (बुधवार)

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पाम ऑयल, अगरवुड और बांस का विकास

2850. श्री तापिर गावः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च, 2025 की तिथि तक राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में कुल कितना क्षेत्रफल लाया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य क्या है और उक्त पहल के अंतर्गत स्थापित नर्सरियों, बीज उद्यानों और प्रसंस्करण अवसंरचना की क्या स्थिति है;

(ख) सरकार द्वारा अगरवुड की खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और असम और त्रिपुरा में संशोधित निर्यात कोटा, जीआई पंजीकरण स्थिति, क्लस्टर विकास तथा उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई केंद्रीकृत लाइसेंसिंग तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्वीकृत बांस क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं की संख्या और मूल्य का कारीगर-प्रशिक्षण कार्यक्रम, बनाई गई बांस उत्पाद श्रंखलाओं और ई-कॉमर्स स्टोरफ्रंट और बी2बी प्लेटफार्म के माध्यम से बाजार-सम्बद्ध पहल सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान इन तीन मूल्य श्रंखलाओं, पाम ऑयल, अगरवुड और बांस के विकास के माध्यम से आजीविका संवर्धन, निर्यात प्रदर्शन और उद्योग विविधीकरण में क्या वास्तविक परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल - ऑयल पाम के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में कुल 68,324 हेक्टेयर संचयी क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती की जा रही है, जिसे वर्ष 2025-26 में 92,543 हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके विस्तार के लिए, 47 नर्सरी बनाई गई हैं और वर्ष 2025-26 के लिए 22 और नर्सरी बनाने को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में बीज उद्यानों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में दो और मिजोरम में एक मिल चालू होने से प्रोसेसिंग कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2025-26 में असम के लिए एक नई मिल को अनुमोदन दिया गया है। मिशन का फोकस एरिया कवरेज बढ़ाना, अच्छी

गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मैटीरियल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके।

(ख) कृषिवानिकी सहित अगर के पेड़ों की खेती राज्यों में लगातार जारी वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ने वर्ष 2024 में किए गए एक मूल्यांकन में उल्लेख किया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निजी भूमि पर लगभग 13.51 करोड़ अगर के पेड़ उगाए गए हैं। इसकी निर्यात संभावना अधिक होने के कारण वर्ष 2023 में एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने वर्ष 2024 में सतत खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार के लिए एक रोडमैप को मंज़ूरी दी है। त्रिपुरा और असम में भू-स्थानिक मैपिंग की सहायता से उत्तर पूर्वी राज्यों को एरिया-एक्सपेंशन प्लान तैयार करने के लिए लिखा गया है, जबकि सीआईटीईएस कन्वेंशन के तहत चिप्स के लिए 1,51,080 कि.ग्रा. तक और तेल के लिए 7,050 कि.ग्रा. तक वार्षिक निर्यात कोटा में वृद्धि करके निर्यात संवर्धन को काफी सुदृढ़ किया गया है। निर्यात को आसान बनाने के लिए, अगरवुड उत्पादों के निर्यात के लिए एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग को डीजीएफटी पोर्टल पर समेकित किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि विपणन निगम) लिमिटेड ने पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के साथ मिलकर जीआई टैगिंग का कार्य भी शुरू किया है। कदमतला (त्रिपुरा) और गोलाघाट (असम) में दो अगरवुड क्लस्टर बनाने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) भी तैयार किया गया है। कुल मिलाकर, इन प्रयासों का उद्देश्य खेती को बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र से अगरवुड निर्यात को बढ़ावा देना है।

(ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद ने अब तक ₹154.03 करोड़ की कुल 23 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल (एनईसीबीडीसी) ने पिछले तीन वर्षों में कुल 4907 बांस कारीगरों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बाजार संपर्क बढ़ाने, उत्पादों को आधुनिक बनाए जाने और उन्हें डिजिटल और रिटेल इकोसिस्टम से जोड़कर पारंपरिक बांस कारीगर क्लस्टर्स को सुदृढ़ करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्लस्टर सुदृढ़ीकरण और एक्सपोर्ट को सुसाध्य बनाकर इंजीनियर्ड बांस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुल 82.50 करोड़ रुपये के व्यय वाली दो परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

(घ) पिछले वर्ष से सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस, ऑयल पाम और अगरवुड वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक पहलें की हैं, जिसमें आजीविका बढ़ाने, निर्यात निष्पादन और उद्योगों के विकास संबंधी मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए तीनों वैल्यू चेन, पाम ऑयल, अगरवुड और बांस का विकास किया गया है, जिसका वर्णन उत्तर के उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) में किया गया है।

*****